Mr. Speaker: What is it that he wants the hon. Minister to be aware of? Hon. Members should elicit certain things.

Shri Sadhan Gupta: I am eliciting information.

Mr. Speaker: I am yet to see what the question is.

Shri Sadhan Gupta: I am asking it.

Bengali documents have to be translated into English and therefore is the hon. Minister contemplating any change in the rules?

The Minister of Home Affairs (Pandit G. B. Pant): Such matters come within the purview of the High Courts.

Shri Sadhan Gupta: The Criminal Procedure Code is there. Is no change contemplated?

सेठ गोविन्द दास : क्या कोई ऐसे नियम हैं कि जिनके कारण यदि कोई हाई कोर्ट अपना काम वहां की अपनी भाषा में करना चाहे तो उसको करने के लिए केन्द्रीय सरकार से इजाजत की जरूरत पड़ती है, और अगर ऐसे कोई नियम हैं तो क्या इस बात का कोई विचार किया जा रहा है कि इन नियमों में इस प्रकार का परिवर्तन कर दिया जाये कि जिससे जो हाई कोर्ट अपनी भाषा में अपनी कार्रवाई करना चाहे वह कर सके ?

पंडित गो० ब० पन्त : कास्टीट्यूशन में यह है कि फैसले और डिग्री वगैरह तो अंग्रेजी में होने चाहिएं । उसके अलावा जो और कार्रवाई होती है उसके लिए प्रेसीडेंट, अगर किसी खास प्रदेश से इस बात का सुझाव आवे तो, इजाजत दे सकते हैं । राजस्थान और केरल में दरअसल विलोनीकरण से पहले से इन भाषाओं में काम होता आया है । इधर किसी जगह कोई खास ऐसी कार्रवाई नहीं की गयी ।

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि मध्य प्रदेश में जब ग्वालियर में हाईकोर्ट था तो उस समय ग्वालियर की हाईकोर्ट अपनी भाषा में काम करती थी, और अभी भी ग्वालियर में हाईकोर्ट की एक बैंच रखी गयी है । क्या ऐसे स्थानों पर कि जहां पहले वहां की भाषाओं में काम होता था, वहां की भाषाओं में काम होने की इजाजत देने का गवर्नमेंट विचार कर रही है ?

पंडित गो० ब० पन्त : अगर कोई प्रादेशिक गवर्नमेंट यहां की गवर्नमेंट को लिखे तो उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा ।

Shri Dasappa: May I know whether any other State other than Rajasthan and Kerala has sought permission to have their own regional language?

Pandit G. B. Pant: So far as I am aware, no.

श्री ब्रज राज सिंह :क्या मैं जान सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार में केन्द्रीय सरकार के पास इस तरह का कोई सुझाव भेजा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में हिन्दी में सब कार्रवाई की जाये ?

पंडित गो० ब० पन्त : जहां तक मुझे मालूम है कि कोई ऐसा सुझाव नहीं भेजा है ।

Shri Yajnik: May I know if Rajkot High Court, which used to conduct its proceedings in Gujerati before the integration of Saurashtra in Bombay, has reverted to the English language only after its integration with Bombay?

Pandit G. B. Pant: Maybe, I cannot say.

निर्वाचनों में प्रचार कार्य

*१६५५. **डा० राम सुभग सिंह** :

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्वाचन आयोग ने यह सलाह दी है कि केन्द्रीय एवं

राज्य सरकारों के मंत्रियों को सरकारी गाड़ियों में सरकारी कर्मचारियों के साथ निर्वाचन के दौरान निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार कार्य के लिये नहीं जाना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस): (क) और (ख). जी, हां ! मुझे पता चला है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने हाल ही में राज्यों के मुख्य मंत्रियों को ऐसी परम्परा स्थापित करने की वांछनीयता के बारे में लिखा कि मंत्रिगण निर्वाचन के दौरान निर्वाचन क्षेत्रों में सरकारी दौरे पर सरकारी गाड़ियों में न जाएं और यदि किसी मंत्री को ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में सरकारी दौरे पर जाना पड़े तो वह अपने दल के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार न करे । मुख्य मंत्रियों ने आयोग को सूचित किया है कि प्रचलित प्रथा के अनुसार ऐसे दौरे जिन पर आपत्ति की जा सकती है सामान्यतया नहीं किये जाते हैं और भविष्य में भी नहीं किये जाएंगे ।

Shri Sadhan Gupta: May I know whether Government have any information about this direction being complied with in the case of the Maudaha bye-election in U.P. and Phalakata bye-election in Jalpaiguri and Cooch Behar Parliamentary bye-election?

Shri Hajarnavis: There is no support to the effect that this is being ignored and is not being implemented.

Shri Hem Barua: Even after the Election Commission's writing to the State Chief Ministers about this, are Government awar of the fact that Ministers in the States are moving in the constituencies, where bye-elections are held recently, actively canvassing for candidates and are using Police and military vans to overshadow the voters ......

Mr. Speaker: It is unfortunate that hon. Members are trying to take advantage of questions for putting across their own views about particular things. Such kind of general questions, *i.e.* that all ministers have gone and all ministers are bad, lead us nowhere. If the hon. Member has a particular case about so-and-so going on a particular date, the hon. Minister may be in a position to reply, but he cannot reply to such questions of a general nature.

It is also not right that such questions are shot at the Minister without any notice.

The general public outside will think as if it is the fact.

Shri Hem Barua: I have got a humble submission. In bye-elections in Assam......

Mr. Speaker: The hon. Member may have a fund of information but it is not relevant. The hon. Member may know something which the hon. Minister may not know.

Shri Hem Barua: Let the hon. Minister say that.

Mr. Speaker: The hon. Minister cannot say that. He must have notice. Therefore individual cases must be brought to his notice. He was not present there. Does the hon. Member say that the hon. Minister was present there? He has to ascertain the facts from the local officers and then place them before the House. If the hon. Member was himself a minister would he answer that question?

The Question Hour is over.

Short Notice Question and Answer

Pakistan's letter to U.N. Security Council on Kashmir

\+

S.N.Q. No. 12. { **Shrimati Ila Palchoudhuri:** / **Shri A. M. Tariq:** / **Shri N. R. Munisamy:**

Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) whether Government of India's attention has been drawn to a letter